PLUTUS IAS

UPSC/ PCS

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

प्लूटस आई.ए.एस. साप्ताहिक करंट अफेयर्स

17/06/2024 से 23/06/2024 तक

THE HINDU

The Indian EXPRESS

पत्र सूचना कार्यालय
PRESS INFORMATION BUREAU
भारत सरकार

कार्यालय

बेसमेंट 8, अप्सरा आर्केड, करोल बाग मेट्रो स्टेशन गेट नंबर - 6, नई दिल्ली 110005

706 प्रथम तल डॉ. मुखर्जी नगर बत्रा सिनेमा के पास दिल्ली - 110009

मोबाइल नं. : +91 84484-40231

वेबसाइट : www.plutusias.com

ईमेल : info@plutsias.com

साप्ताहिक करंट अफेयर्स

विषय सूची

1. बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य की मान्यता देने की मांग करना..... 1
2. G7 समूह देशों का 50वाँ शिखर सम्मेलन..... 4
3. भारतीय वायु सेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास : तरंग शक्ति – 2024 7
4. भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनाम विश्व मगरमच्छ दिवस 2024..... 9
5. डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार 10
6. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 13

करंट अफेयर्स जून 2024

बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य की मान्यता देने की मांग करना

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय संविधान, भारत में केंद्र – राज्य संबंध, संघवाद, विशेष राज्य का दर्ज़ा, विशेष श्रेणी की राज्य की चुनौतियाँ ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' विशेष श्रेणी का राज्य की मान्यता मिलना , बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण 2022, योजना आयोग, अनुच्छेद 370, केंद्र प्रायोजित योजना ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य की मान्यता देने की मांग करना ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- बिहार के मुख्यमंत्री ने हाल ही में केंद्र सरकार से राज्य के लिए विशेष श्रेणी की स्थिति प्रदान करने की पुरानी मांग को पुनः उठाया है , जिसका उद्देश्य राज्य को प्राप्त होने वाले कर राजस्व प्राप्ति में वृद्धि करना है।

भारत में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य होने अर्थ क्या होता है ?

- भारत में किसी भी राज्य को 'विशेष श्रेणी का राज्य' होने का मान्यता एक प्रकार की वह पहचान है जो केंद्र सरकार उन राज्यों को देती है जो भौगोलिक या सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं।
- इससे उन राज्यों को अपने राज्य में विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलती है।
- भारत के मूल संविधान में इसका कोई प्रावधान नहीं है।
- यह 1969 में पाँचवें वित्त आयोग की सलाह पर शुरू किया गया।
- भारत में सबसे पहले वर्ष 1969 में जम्मू-कश्मीर, असम और नगालैंड को यह मान्यता प्रदान किया गया था।
- हाल ही में तेलंगाना भारत का वह नवीनतम राज्य है जिसे यह मान्यता प्राप्त हुआ है।
- इस संदर्भ में यह बात गौर करने लायक यह होती है कि 'विशेष स्थिति' और 'विशेष श्रेणी का राज्य' होने का मान्यता मिलना दोनों अलग – अलग है।
- 'विशेष स्थिति' में कुछ ख़ास कानूनी और सरकारी प्राधिकरण मिलते हैं, पर 'विशेष श्रेणी' सिर्फ वित्तीय और आर्थिक सहायता और संसाधनों से संबंधित होता है।
- SCS, विशेष स्थिति से भिन्न है जो कि उन्नत विधायी तथा राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है, जबकि SCS केवल आर्थिक एवं वित्तीय पहलुओं से संबंधित है।
- उदाहरण के लिए अनुच्छेद 370 के निरस्त होने से पहले तक भारत में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्ज़ा प्राप्त था।

भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक अहर्ताएं अथवा मापदंड :

भारत में गाडगिल समिति की सिफारिश पर आधारित विशेष राज्य का मान्यता प्राप्त करने के मापदंड निम्नलिखित है –

- वह राज्य पहाड़ी इलाका से संबंधित हो।
- उस राज्य की जनसंख्या घनत्व कम हो और/या उस राज्य में जनजातियों की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निवास करती हो।
- उस राज्य की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हो और उन सीमाओं का सामरिक दृष्टिकोण से अवस्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण हो।
- वह राज्य आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन की स्थिति में हो।
- राज्य के वित्त अथवा राजस्व प्राप्ति की अव्यवहार्य प्रकृति की हो।

भारत में किसी भी राज्य को विशेष श्रेणी का राज्य का मान्यता मिलने से प्राप्त होने वाला लाभ :

- उस राज्य को अन्य राज्यों के मामले में %60 या %75 की तुलना में केंद्र प्रायोजित योजना में आवश्यक निधि का %90 विशेष श्रेणी के राज्यों को भुगतान किया जाता है, जबकि शेष निधि राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है।
- वित्तीय वर्ष में अव्ययित निधि व्यपगत नहीं होती है और इसे आगे बढ़ाया जाता है।
- इन राज्यों को उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क, आयकर एवं निगम कर में महत्त्वपूर्ण छूट प्रदान की जाती हैं।
- केंद्र के सकल बजट का %30 विशेष श्रेणी के राज्यों को प्रदान किया जाता है।

बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य की मान्यता (SCS) मिलने की मांग करने के लिए दिए जाने वाला तर्क :

बिहार को विशेष श्रेणी का राज्य (SCS) का दर्जा देने की मांग के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं –

ऐतिहासिक एवं संरचनात्मक चुनौतियाँ :

- **आर्थिक कठिनाइयाँ :** बिहार को आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि औद्योगिक विकास की कमी और सीमित निवेश के अवसर।
- **बिहार राज्य के विभाजन के परिणाम :** बिहार राज्य विभाजन के बाद, अधिकांश उद्योग झारखंड राज्य में चले गए, जिससे बिहार में रोजगार और आर्थिक विकास की समस्याएँ बढ़ गईं।

प्राकृतिक आपदाएँ :

- **बाढ़ और सूखा :** बिहार को उत्तर में बाढ़ और दक्षिण में सूखे जैसी गंभीर प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इन आपदाओं से कृषि गतिविधियाँ बाधित होती हैं और सिंचाई सुविधाएँ अपर्याप्त होती हैं, जिससे आजीविका और आर्थिक स्थिरता पर असर पड़ता है।

बुनियादी ढाँचे का अभाव :

- **अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा :** बिहार का अविकसित बुनियादी ढाँचा राज्य के समग्र विकास में बाधा डालता है, जिसमें खराब सड़कों का नेटवर्क, सीमित स्वास्थ्य सेवाएँ और शैक्षिक सुविधाओं की कमी शामिल है।
- **रघुराम राजन समिति :** वर्ष 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने बिहार को "अल्प विकसित श्रेणी" में रखा।

निर्धनता तथा सामाजिक विकास :

- **उच्च निर्धनता दर :** बिहार राज्य में निर्धनता दर उच्च है और वहां की बहुसंख्यक परिवार गरीबी रेखा से नीचे में जीवन यापन कर रहे हैं।
- **नीति आयोग का सर्वेक्षण :** नीति आयोग के एक हालिया सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार निर्धन राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर है, जहाँ वर्ष 23-2022 में बहुआयामी निर्धनता %26.59 थी, जो राष्ट्रीय औसत %11.28 की तुलना में अत्यधिक है।
- **प्रति व्यक्ति GDP का निम्न होना :** बिहार की प्रति व्यक्ति GDP वर्ष 23-2022 के लिए राष्ट्रीय औसत 1,69,496 रुपए की तुलना में मात्र 60,000 रुपए है।
- **मानव विकास सूचकांक :** भारत के विभिन्न राज्यों की तुलना में बिहार विभिन्न मानव विकास सूचकांकों में भी काफी पीछे है।

विकास के लिए वित्त पोषण :

- **अपर्याप्त वित्तीय सहायता :** SCS की मांग करना केंद्र सरकार से पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने का एक साधन है, जिससे दीर्घकालिक सामाजिक-आर्थिक चुनौतियों से निपटा जा सके।
- **राज्य सरकार का अनुमान :** बिहार सरकार के अनुसार, विशेष श्रेणी का दर्जा मिलने से राज्य को पाँच वर्षों में गरीब परिवारों के कल्याण पर खर्च के लिए 94 लाख करोड़ रुपए के अलावा अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ रुपए प्राप्त होंगे।

बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) नहीं देने के पीछे क्या तर्क हैं ?

बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा (SCS) नहीं देने के पीछे कुछ मुख्य तर्क निम्नलिखित है –

- **धनराशि का दुरुपयोग :** भारत में विभिन्न आलोचकों का मानना है कि अतिरिक्त धन से खराब नीतियों को प्रोत्साहन मिल सकता है।
- **कानून और व्यवस्था :** बिहार में प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त विभिन्न समस्याएं बिहार के बहु स्तरीय विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं।
- **केंद्रीय सरकार द्वारा वित्त का हस्तांतरण :** 14वें वित्त आयोग के अनुसार, केंद्र पहले से ही राज्यों को कुल प्राप्त राजस्व का %42 कर हस्तांतरित कर चुका है, और SCS से केंद्रीय कोष पर ही अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे केंद्र सरकार को अपने स्तर पर क्रियान्वित करने वाले विकास योजनाओं के लिए पर्याप्त राशी की कमी हो सकती है।
- **बिहार में विकास की गति का स्तर तीव्रतम होना :** बिहार पहले से ही तेजी से प्रगति कर रहा है, वित्तीय वर्ष 23-2022 में बिहार के GDP में %10.6 की वृद्धि हुई है।
- **SCS का मानदंड का पूरा नहीं करना :** SCS प्राप्ति के मानकों में पहाड़ी क्षेत्रों की मुश्किलें का प्रमुख होना हैं, जो बिहार में नहीं हैं।
- **14वें वित्त आयोग की सिफारिशें :** केंद्र सरकार 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर काम करते हुए भारत के विभिन्न राज्यों के SCS के प्रस्तावों को ख़ारिज करती रहती है, क्योंकि इससे केंद्र सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है।

बिहार को विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त होने (SCS) से मिलने वाली सहायता से तात्कालिक रूप से तो समस्या का समाधान हो सकता है, परन्तु स्थायी समाधान के लिए प्रशासनिक सुधारों पर ज़ोर देना ज़रूरी है।

बिहार के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्य जो SCS की मांग कर रहे हैं :

- भारत के कुछ अन्य राज्य भी विशेष दर्जे की मांग कर रहे हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- वर्ष 2014 में विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश हैदराबाद को तेलंगाना में स्थानांतरित होने से उत्पन्न राजस्व की हानि के कारण SCS की मांग कर रहा है।
- इसी प्रकार, ओडिशा प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवातों और अपनी बड़ी जनजातीय आबादी (लगभग %22) के कारण SCS की मांग अनुरोध करता रहता है।

विशेष श्रेणी का राज्य (SCS) का दर्जा मिलने की राह में मुख्य चुनौतियाँ :

विशेष श्रेणी का राज्य (SCS) का दर्जा मिलने की राह में मुख्य चुनौतियाँ निम्नलिखित है –

- **अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता :** SCS का दर्जा प्राप्त करने के लिए, राज्यों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता की जरूरत होती है, जो केंद्रीय संसाधनों पर अतिरिक्त भार डाल सकती है।
- **केंद्रीय सहायता पर निर्भरता :** SCS के लाभ से राज्य केंद्रीय सहायता पर अधिक निर्भर हो सकते हैं, जो स्व-निर्भरता और स्वतंत्र आर्थिक प्रगति में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
- **कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ :** SCS मिलने के पश्चात्, प्रशासनिक दक्षता की कमी, भ्रष्टाचार, और उपयुक्त नियोजन की कमी से, सही ढंग से निधि का प्रबंधन मुश्किल हो सकता है।

समाधान / आगे की राह :

- भारत में किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के संदर्भ में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए SCS प्रदान करने के मानदंडों पर पुनर्विचार की आवश्यकता है।
- वर्ष 2013 में केंद्र सरकार द्वारा गठित रघुराम राजन समिति ने SCS के स्थान पर निधियों के हस्तांतरण के लिए 'बहु-आयामी सूचकांक' पर आधारित नई पद्धति का सुझाव दिया था।
- इस पद्धति से राज्यों के सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन को दूर करने के उपायों पर पुनर्विचार किया जा सकता है।
- आत्मनिर्भरता और आर्थिक विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार पर राज्यों की निर्भरता को कम करने वाली नीतियों को लागू करना चाहिए। साथ ही, राज्यों के राजस्व स्रोतों में विविधता लाने पर जोर देना चाहिए।
- विश्लेषकों का सुझाव है कि सतत् आर्थिक विकास के लिए बिहार में विधि के शासन की आवश्यकता है। भारत में राज्यों को व्यापक विकास योजनाएँ बनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
- **शिक्षा में सुधार :**
  - प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास (ICDS केंद्र), शिक्षक प्रशिक्षण और शिक्षण पद्धति में सुधार पर ध्यान केंद्रित करने वाली RTE फोरम की सिफारिशों पर अमल करना चाहिए।
  - अधिक संवादात्मक और प्रौद्योगिकी आधारित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
- **कौशल विकास एवं रोजगार सृजन :**
  - बिहार के युवाओं के कौशल विकास पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
  - बिहार में व्यवसायों को आकर्षित करने और रोजगार सृजन हेतु SIPB (सिंगल-विंडो इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड) जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देना चाहिए।
  - बिहार में कौशल विकास एवं संबंधित कौशल पहलों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
- **बुनियादी ढाँचे का विकास :**
  - बिहार में समग्र विकास के लिए बेहतर बुनियादी ढाँचे का होना आवश्यक है।
  - बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए बेहतर सिंचाई प्रणालियों पर ध्यान देना चाहिए।
  - ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क स्थापित करने, निवेश आकर्षित करने और कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत परिवहन नेटवर्क विकसित करना चाहिए।
- **महिला सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशन :**
  - बिहार में लैंगिक समानता और सामाजिक स्तरीकरण की चुनौतियों का सामना करने वाली विधियों के बेहतर प्रवर्तन और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना चाहिए।
  - बिहार में महिलाओं की शिक्षा, कौशल विकास और वित्तीय समावेशन पर ध्यान देना चाहिए।
  - इन उपायों से बिहार राज्य की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और बिहार के समग्र विकास की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकेंगे।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्ज़ा (SCS) देने के संदर्भ में निम्नलिखित स्थितियों पर विचार कीजिए।

1. उस राज्य की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ जुड़ी हुई हो।
2. उस राज्य का आर्थिक तथा आधारभूत संरचना में पिछड़ापन होना।
3. राज्य की जनसंख्या का घनत्व का अधिक होना।
4. उस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा निवास करती हो।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2 , 3 और 4

C. केवल 3 और 4

D. केवल 1 और 2

उत्तर – D .

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत के राजकोषीय संघवाद और केंद्र – राज्य संबंध के संदर्भ में यह चर्चा कीजिए कि भारत में राज्यों को विशेष श्रेणी का राज्य का दर्ज़ा (SCS) देने में मुख्य चुनौतियाँ क्या है और उसका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

G7 समूह देशों का 50वाँ शिखर सम्मेलन

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' अंतर्राष्ट्रीय – संबंध, महत्त्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, वैश्विक समूह, द्विपक्षीय समूह और समझौते, भारत की विदेश नीति, क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में क्वाड का महत्व, वैश्विक चुनौतियों से निपटने में G7 शिखर सम्मेलन की भूमिका, जलवायु परिवर्तन और वैश्विक सुरक्षा के बीच संबंध ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' G7 शिखर सम्मेलन, हिंद – प्रशांत क्षेत्र का सामरिक महत्त्व ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' G7 समूह देशों का 50वाँ शिखर सम्मेलन ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में इटली में 13 से 15 जून, 2024 तक आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया।
- यह शिखर सम्मेलन G7 समूह के देशों की 50वीं वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था।
- भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने तीसरे कार्यकाल में पुन: प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद, यह उनकी पहली विदेशी यात्रा थी।
- G7 का सदस्य न होते हुए भी, भारत पहले भी 2021 ,2019, और 2022 में क्रमश: फ्राँस, यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी में हुए G7 सम्मेलनों में मेहमान के रूप में सम्मिलित हुआ है।

G-7 का परिचय और मुख्य उद्देश्य :

- **G7-** समूह दुनिया के सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के देशों का एकअंतरराष्ट्रीय समूह और अनौपचारिक मंच है।
- इसमें **कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य (यूके)** शामिल हैं, साथ ही **यूरोपीय संघ (EU)** भी इस समूह के एक 'गैर-सूचीबद्ध सदस्य' के रूप में माना जाता है।
- **G7-** का मुख्य उद्देश्य **वैश्विक समस्याओं** विशेषकर **आर्थिक मुद्दों** पर चर्चा करना और कभी-कभी समन्वित कार्रवाई करना होता है।
- **G7-** की स्थापना 1970 के दशक में हुआ था।
- प्रारंभ में 6 प्रमुख औद्योगिक देशों के साथ, और 1976 में **कनाडा** के सम्मिलित होने के बाद इस **G7-** का गठन हुआ था।
- 1998 में **रूस** के सम्मिलित होने पर **G7- 'G8-'** के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था, परंतु सन 2014 में **क्रीमिया** पर कब्जा करने के प्रतिक्रिया में **रूस** को इस समूह से निष्कासित कर यह **G7-** में पुन: परिवर्तित हो गया।
- **G7-** का शिखर सम्मेलन का आयोजन हर साल होता है, जहाँ इस समूह के सदस्यों में से प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।

G-7 का स्वरूप :

- **अनौपचारिक समूह :** G7- एक ऐसा समूह है जो किसी औपचारिक संधि के दायरे में नहीं आता है और इसमें कोई स्थायी प्रशासनिक संरचना नहीं होती है। प्रत्येक सदस्य देश (सम्मेलन की मेजबानी करने वाला) बारी-बारी से मीटिंग्स का संचालन करता है।
- **सर्वसम्मति से निर्णय :** G7- की प्रभावशीलता इसके सदस्यों के आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व से प्रेरित होती है, और महत्वपूर्ण मुद्दों पर सहमति से प्राप्त समर्थन से विश्व-स्तर पर प्रभाव पैदा कर सकती है।
- **सीमित कानूनी शक्ति :** G7- सीधे कोई कानून प्रस्तुत नहीं कर सकता, परंतु इसके प्रस्तावों और समन्वित क्रियाओं का अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता है, और यह विश्व-स्तरीय मुद्दों पर प्रमुख पहलों को आकार देने में महत्वपूर्ण हो सकता है

50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित प्रमुख बिंदु :

- इटली में हुए 50वें G7 शिखर सम्मेलन में शामिल विभिन्न देशों के नेताओं ने पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (Partnership for Global Infrastructure and Investment- PGII) के तहत विकासशील देशों के लिए **600 बिलियन डॉलर** की सहायता और भारत – मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना को समर्थन और प्रोत्साहन देने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को व्यक्त करने की आवश्यकता को जताया।
- पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट (Partnership for Global Infrastructure and Investment- PGII) का मुख्य उद्देश्य निम्न-मध्यम आय वाले देशों में बुनियादी संरचना को मजबूत करना है।
- IMEC परियोजना भारत, मध्य पूर्व, और यूरोप के बीच परिवहन संपर्क को सुदृढ़ करने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
- IMEC का लक्ष्य भारत, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले रेल, सड़क और समुद्री मार्ग सहित एक व्यापक परिवहन नेटवर्क स्थापित करना है।

भारत – मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) परियोजना :

- सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में इस पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- यह परियोजना PGII का हिस्सा है।
- प्रस्तावित IMEC में रेलमार्ग, शिप-टू-रेल नेटवर्क और सड़क परिवहन मार्ग शामिल होंगे जो 2 गलियारों तक विस्तृत होंगे, अर्थात् पूर्वी गलियारा (East Corridor): यह भारत को अरब खाड़ी से जोड़ता है और उत्तरी गलियारा (Northern Corridor): यह खाड़ी देशों को यूरोप से जोड़ता है।
- IMEC गलियारे में एक विद्युत केबल, एक हाइड्रोजन पाइपलाइन और एक हाई-स्पीड डेटा केबल भी शामिल होंगे।
- भारत, अमेरिका, सऊदी अरब, UAE, यूरोपीय संघ, इटली, फ्राँस और जर्मनी IMEC के हस्ताक्षरकर्त्ता देश हैं।

अफ्रीका और एशिया में कई महत्वपूर्ण आधारभूत अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन :

G7 समूह ने अफ्रीका और एशिया में कई प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं का समर्थन किया है, जिनमें शामिल हैं –

- **लोबिटो कॉरिडोर :** यह कॉरिडोर अंगोला के अटलांटिक तट पर स्थित लोबिटो के बंदरगाह शहर से कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य (DRC) और ज़ाम्बिया तक फैला हुआ है।
- **लूज़ोन कॉरिडोर :** यह कॉरिडोर फिलीपींस के सबसे बड़े द्वीप लूज़ोन पर स्थित है, जो एक महत्वपूर्ण आर्थिक और अवसंरचना क्षेत्र है। लूज़ोन फिलीपींस का सबसे बड़ा और सबसे अधिक आबादी वाला द्वीप है।
- **मिडल कॉरिडोर :** इसे ट्रांस-कैस्पियन अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मार्ग (TITR) के नाम से भी जाना जाता है, जो यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला एक प्रमुख लॉजिस्टिक्स/रसद और प्रमुख परिवहन संपर्क मार्ग प्रदान करता है।
- **ग्रेट ग्रीन वॉल :** यह अफ्रीका के साहेल क्षेत्र में मरुस्थलीकरण को रोकने, जैव-विविधता में सुधार, और स्थानीय समुदायों के लिए आर्थिक संभावनाओं को मजबूत करने के लिए अफ्रीका में पश्चिम से पूर्व तक वृक्षों की एक श्रृंखला को विकसित करना है।
- G7- समूह देशों के नेताओं ने AI गवर्नेंस के क्षेत्र में अधिक समन्वय और सामंजस्य बनाने के प्रति संकल्पित हैं, जिससे अधिक सुनिश्चितता, पारदर्शिता, और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके। इसका मकसद जोखिमों का प्रबंधन ऐसे करना है जो नवाचार को प्रोत्साहन दे और साथ ही स्वस्थ, समावेशी, और दीर्घकालीन आर्थिक प्रगति को बल प्रदान करे।
- असाधारण राजस्व त्वरण (Extraordinary Revenue Acceleration- ERA) ऋण: के माध्यम से, G7- ने 2024 के अंत तक यूक्रेन को 50 बिलियन USD की अतिरिक्त सहायता प्रदान करने की सहमति प्रकट की है।

भारत की G7- में भूमिका :

भारत की G7- में भूमिका इस प्रकार महत्वपूर्ण है –

- **आर्थिक महत्त्व :** 3.57 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के GDP के साथ, भारत की अर्थव्यवस्था G7- के कई सदस्यों से बड़ी है। IMF के अनुसार, यह दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। इसका युवा कार्यबल, मार्केट पोटेंशियल, कम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और बिजनेस-फ्रेंडली परिस्थितियाँ इसे निवेश के लिए प्रमुख स्थान बनाती हैं।
- **सामरिक महत्त्व :** हिंद-प्रशांत क्षेत्र में, भारत पश्चिमी देशों के लिए चीन के प्रसार को संतुलित करने में महत्वपूर्ण है। इसकी महत्वपूर्ण साझेदारियाँ, खासकर हिंद महासागर में, G7- समूह के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करती हैं।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **ऊर्जा संक्रमण :** रूसी तेल को सस्ते में प्राप्त करके, पुन: परिष्कृत करके, और फिर यूरोप को सप्लाई करके, भारत ने यूक्रेन संकट के मद्देनजर प्रकोपित हुए ऊर्जा संक्रमण में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की है, जिससे G7- समूह के समक्ष उसका महत्वपूर्ण सहयोगी होना प्रमाणित होता है।

रूस – यूक्रेन संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका में भारत :

- भारत की रूस और पश्चिमी देशों के साथ मजबूत साझेदारी और निष्पक्ष दृष्टिकोण उसे यूक्रेन संकट में मध्यस्थ के तौर पर एक अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं।
- भारत, संवाद और कूटनीति के माध्यम से, संघर्ष का समाधान खोजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

1973-74 का तेल संकट :

1973-74 का तेल संकट वह समय था जब तेल की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी हुई और आपूर्ति में कमी आई, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हुईं।

कारण :

- **योम किप्पुर युद्ध :** सन 1973 में, मिस्र और सीरिया ने इज़रायल पर हमला किया। अमेरिका के इज़रायल को सहायता प्रदान करने पर, OPEC (पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन) ने तेल को एक राजनीतिक हथियार के रूप में प्रयोग किया।

OPEC की कार्रवाई :

- **तेल प्रतिबंध :** OPEC, मुख्यत: इसके अरब सदस्यों, ने इज़रायल का समर्थन करने वाले देशों पर प्रतिबंध लगा दिए।
- **उत्पादन में कमी :** OPEC ने समग्र उत्पादन में कमी की, जिससे तेल की आपूर्ति में संकुचन हुआ था।

प्रभाव :

- **आपूर्ति में कमी :** प्रतिबंध और उत्पादन में कटौती के कारण वैश्विक स्तर पर तेल की कमी हो गई। कई देशों में गैस स्टेशनों पर लंबी कतारें लग गईं और राशनिंग आवश्यक हो गई।
- **मूल्य वृद्धि :** तेल की उपलब्धता कम होने से कीमतों में भारी वृद्धि (3 अमेरिकी डॉलर से 11 अमेरिकी डॉलर तक) हुई।
- **आर्थिक मंदी :** तेल की बढ़ती कीमतों का व्यापक असर हुआ था । परिवहन लागत में वृद्धि हुई, जिससे वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ गईं। इससे कई देशों में मुद्रास्फीति और आर्थिक स्थिरता को झटका लगा।

पश्चिम और चीन-रूस के बीच शक्ति संघर्ष को संतुलित करने में भारत के सामने चुनौतियाँ :

- **रक्षा निर्भरता :** %60 से अधिक सैन्य उपकरणों के लिए भारत की रूस पर निर्भरता एक जटिल स्थिति उत्पन्न करती है। पश्चिमी देशों और रूस के बीच तनावपूर्ण संबंध आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर सकते हैं और भारत को अपनी रक्षा साझेदारी में विविधता लाने हेतु विवश कर सकते हैं।
- **आर्थिक अंतर-निर्भरता :** अमेरिका और चीन दोनों के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने से भारत पर संभावित रूप से दबाव बढ़ सकता है। इन प्रतिस्पर्द्धी संस्थाओं के साथ व्यापार संबंधों को संतुलित करना महत्वपूर्ण होगा।
- **भिन्न दृष्टिकोण :** रूस और चीन का सामना कैसे किया जाए इस बारे में पश्चिमी देशों के बीच व्याप्त मतभेद भारत के लिए अनिश्चितता पैदा करते हैं। एक गुट के साथ बहुत अधिक निकटता से जुड़ना दूसरे गुट को अलग-थलग कर सकता है।
- **घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल :** पश्चिमी लोकतंत्रों में आंतरिक राजनीतिक विभाजन नीतिगत असंगतियों को जन्म दे सकता है, जिससे भारत की रणनीतिक गणनाएँ और अधिक जटिल हो सकती हैं।
- **सीमा विवाद :** चीन के साथ अनसुलझे क्षेत्रीय विवाद, साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता से भारत के लिए सुरक्षा संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं।
- **भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता :** इस क्षेत्र में अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारत को ऐसे मुद्दों पर किसी एक पक्ष का समर्थन करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है जो संभवतः प्रत्यक्ष रूप से इसके राष्ट्रीय हितों के अनुकूल न हों।

निष्कर्ष :

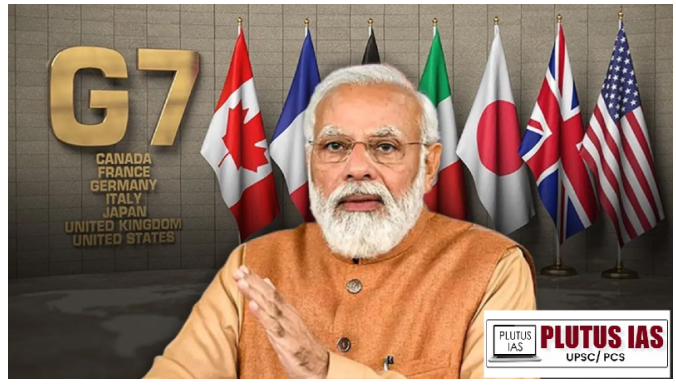

- भारत की G7 में सहभागिता आर्थिक वृद्धि, वैश्विक राजनीति और सामरिक चुनौतियों के प्रति एक महत्वपूर्ण कदम है।
- जो G7 समूह में भारत का योगदान आर्थिक विकास, वैश्विक नीति, और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर काफी महत्वपूर्ण है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपनी प्रमुख स्थिति और यूरोपीय ऊर्जा संकट में सक्रिय भूमिका के माध्यम से, संघर्षों में मध्यस्थ के रूप में भारत का प्रभाव G7 समिट में काफी निर्णायक सिद्ध हो सकता है।
- दुनिया के बदलते परिदृश्य में, G7 के साथ मिलकर भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की नई दिशा को प्रभावित करेगा।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- वैश्विक परिप्रेक्ष्य में परिवर्तन के साथ, G7 के साथ भारत का सहयोग अंतर्राष्ट्रीय सहमति के निर्माण में केंद्रीय होगा।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. G7 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. इस शिखर सम्मेलन का आयोजन तीन – तीन साल के अंतराल पर होता है।
2. इसके प्रत्येक सदस्य देश , बारी-बारी से इसकी मेजबानी करता है।
3. भारत G7 शिखर सम्मेलनों में मेहमान के रूप में सम्मिलित हुआ है।
4. सन 1998 में रूस के सम्मिलित होने पर G7- को 'G8-' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 1 और 3

D. केवल 2 और 4

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q. 1. G7 समूह सदस्य देशों के बीच सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि G7 समूह में भारत की भागीदारी का क्या महत्त्व है और भारत के समक्ष क्या चुनौतियाँ विद्यमान है? तर्कसंगत चर्चा कीजिए। (UPSC – 2021 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारतीय वायु सेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास : तरंग शक्ति – 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' भारत की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से संबंधित मुद्दे , विभिन्न सुरक्षा बल, एजेंसियां और उनका अधिदेश ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' अभ्यास तरंग शक्ति – 2024 , रेड फ्लैग अभ्यास ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारतीय वायु सेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास : तरंग शक्ति – 2024 ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- भारतीय वायु सेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, तरंग शक्ति – 2024, को भारत में ही अगस्त महीने में आयोजित किया जाएगा।
- वायु सेना के इस पहले बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, तरंग शक्ति2024- में कुल 10 देश भाग लेंगे तथा इसमें कुछ अन्य देश पर्यवेक्षक के रूप में भी शामिल होंगे।
- यह बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास अमेरिका द्वारा आयोजित रेड फ्लैग अभ्यास से प्रेरित है।

अभ्यास तरंग शक्ति – 2024 :

- अभ्यास तरंग शक्ति को मूल रूप से वर्ष 2023 के अंत में आयोजित किया जाना था, किन्तु कुछ कतिपय कारणों से इस अभ्यास को 2023 में स्थगित कर दिया गया था।
- अब यह वायु अभ्यास दो अलग-अलग चरणों में आयोजित किया जाएगा।
- **प्रथम चरण :** भारतीय वायु सेना का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास, तरंग शक्ति – 2024, को भारत में प्रथम चरण के तहत अगस्त के प्रथम दो सप्ताह के दौरान दक्षिण भारत में आयोजित किया जाएगा।
- **द्वितीय चरण :** वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 को द्वितीय चरण के तहत भारत के पश्चिमी क्षेत्र में अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक आयोजित किया जाएगा।
- कुछ देश दोनों चरणों में भाग लेंगे, जिससे व्यापक प्रशिक्षण परिदृश्य तैयार होगा, जबकि कुछ अन्य देश परिचालन उद्देश्यों के आधार पर विशिष्ट चरणों में भाग लेंगे।
- यह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है।
- **उद्देश्य :** इस अभ्यास का उद्देश्य उन मित्र देशों को आमंत्रित करना है जिनके साथ भारतीय वायुसेना नियमित रूप से संपर्क रखती है और जिनके बीच कुछ हद तक अंतर-संचालन क्षमता है।
- **अभ्यास तरंग शक्ति – 2024 में भाग लेने वाले देश :** ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, जापान, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।
- इसमें जर्मनी द्वारा A400-M विमान का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसे मध्यम परिवहन विमान की श्रेणी में खुले टेंडर के संभावित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।
- भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित होने वाले इस अभ्यास का मुख्य

उद्देश्य पेशेवर बातचीत को बढ़ावा देना, इसमें भाग लेने वाले विभिन्न बलों के रोजगार दर्शन को समृद्ध करना और मूल्यवान अंतर्दृष्टि के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाना है।

- यह इन देशों के लिए सहयोग करने तथा अपनी सामरिक और परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने का एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है।
- हाल ही में जून 2024 में, भारतीय वायु सेना ने अलास्का में 'रेड फ्लैग' हवाई अभ्यास के दूसरे संस्करण में भाग लिया, जो 4 से 14 जून 2024 तक चला।
- इस अभ्यास में भारतीय राफेल विमानों ने सिंगापुर और अमेरिकी विमानों के साथ मिलकर संयुक्त मिशनों में हिस्सा लिया।
- इन संयुक्त मिशनों का उद्देश्य बियॉन्ड विजुअल रेंज परिस्थितियों में काउंटर एयर हमलों का प्रतिकार करना, उन्हें रोकना और हवाई सुरक्षा की क्षमता को मजबूत करना था।
- इन संयुक्त मिशनोंi में राफेल विमानों का उपयोग करते हुए बियॉन्ड विजुअल रेंज स्थितियों में आक्रामक काउंटर एयर और एयर डिफेंस भूमिकाओं में बड़े पैमाने पर संलग्नता के मिशनों का संचालन किया गया था।

रेड फ्लैग अभ्यास क्या है ?

- रेड फ्लैग अभ्यास (जिसे रेड फ्लैग – नेलिस भी कहा जाता है) संयुक्त राज्य वायुसेना (USAF) द्वारा वर्ष भर में कई बार दो-सप्ताह के लिए आयोजित होने वाला एक उन्नत वायुयुद्ध प्रशिक्षण अभ्यास है।
- इसका उद्देश्य सैन्य वायुयान पायलटों और अन्य उड़ान के कर्मचारियों के लिए वास्तविक वायुयुद्ध प्रशिक्षण प्रदान करना है, जो संयुक्त राज्य और सहयोगी देशों से हैं।
- हर वर्ष, तीन से छह रेड फ्लैग अभ्यास नेलिस एयर फोर्स बेस, नेवाडा में आयोजित किए जाते हैं, जबकि और चार अधिक, जिन्हें रेड फ्लैग – अलास्का कहा जाता है, एयल्सन एयर फोर्स बेस, अलास्का में आयोजित किए जाते हैं।
- इसे पहली बार 29 नवंबर 1975 को आयोजित किया गया था, रेड फ्लैग अभ्यास संयुक्त राज्य वायुसेना (USAF), संयुक्त राज्य नौसेना (USN), संयुक्त राज्य मैरीन कोर (USMC), संयुक्त राज्य सेना (USA) और कई सहयोगी राष्ट्रों की वायुयान के कर्मचारियों को एक साथ एक मंच पर साथ लाता है।
- रेड फ्लैग अभ्यास नेलिस के तहत संयुक्त राज्य वायुसेना युद्ध केंद्र (USAFWC) के नियंत्रण में आयोजित होते हैं। इन्हें 57 विंग (57 WG) के 414 वायुयान प्रशिक्षण वायुसेना (414 CTS) द्वारा चलाया जाता है।
- **यूएसएएफ द्वारा आयोजित :** हाल ही में अलास्का के एयेल्सन एयर फोर्स बेस पर संपन्न हुए रेड फ्लैग अभ्यास में कई अंतर्राष्ट्रीय भागीदारियां शामिल थीं।
- **भारतीय वायुसेना की तैनाती :** भारतीय वायुसेना ने इस अभ्यास के लिए आठ राफेल लड़ाकू विमानों को तैनात किया, जिनका समर्थन आईएल78- मध्य-हवा रिफ्यूलर्स और सी17- ग्लोबमास्टर विमानों द्वारा किया गया।
- **युद्ध सिमुलेशन :** इस अभ्यास में हवाई युद्ध के विभिन्न परिदृश्यों को शामिल किया गया, जिसमें लाल और नीली सेनाएं क्रमशः रक्षात्मक और आक्रामक भूमिकाओं का अनुकरण करती हैं।

अभ्यास तरंग शक्ति – 2024 का महत्व :

- अभ्यास तरंग शक्ति – 2024 के आयोजन में उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और सैन्य तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन किया जाता है।
- इसके साथ ही यह सहभागी देशों के मध्य उपकरणों की प्रभावशीलता और समन्वय का परीक्षण भी करता है।
- यह अभ्यास उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जिसमें लड़ाकू जेट, परिवहन विमान, और हवाई ईंधन भरने की प्रणालियाँ शामिल हैं।
- यह अभ्यास विभिन्न प्रतिभागी देशों को बहुराष्ट्रीय परिवेश में अपने उपकरणों की प्रभावशीलता और अंतर-संचालनशीलता को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान करता है।
- इस अभ्यास से बदलते भू – रणनीतिक देशों के क्षेत्रीय स्थिरता में वृद्धि होगी और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।
- यह अभ्यास के माध्यम से वैश्विक सुरक्षा पहलों में एक प्रमुख साझेदार के रूप में भारत की भूमिका को सुदृढ़ करता है और इसमें भागीदार देशों के साथ भारत के राजनयिक संबंधों को मजबूत करता है।

स्रोत – द हिंदू एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अभ्यास तरंग शक्ति 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह भारतीय वायु सेना द्वारा आयोजित होने वाला पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास है।
2. यह भारत में चार चरणों में आयोजित होगा।

3. इसका आयोजन भारतीय थल सेना द्वारा अन्य देशों के थल सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास के रूप में किया जायेगा।

4. इस अभ्यास का द्वितीय चरण अगस्त के अंत से सितंबर के मध्य तक भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आयोजित किया जाएगा।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. केवल 2 और 4

D. केवल 1 और 4

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अभ्यास तरंग शक्ति के महत्व को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह किस प्रकार भारत के आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए उन्नत सैन्य प्रौद्योगिकियों और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक मंच है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनाम विश्व मगरमच्छ दिवस 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 3 के अंतर्गत ' पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव-विविधता और पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण प्रदूषण ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 , भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना. जैव-विविधता और पर्यावरण संरक्षण ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना बनाम विश्व मगरमच्छ दिवस 2024 ' से संबंधित है।)

ख़बरों में क्यों ?

- विश्व मगरमच्छ दिवस, जिसे विश्व मगर दिवस के रूप में भी जाना जाता है, को संपूर्ण विश्व में हर साल 17 जून को मनाया जाता है।
- विश्व मगरमच्छ दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में लुप्तप्राय मगरमच्छों और घड़ियालों के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उनकी दुर्दशा को उजागर करने का एक वैश्विक अभियान होता है।
- वार्षिक सरीसृप जनगणना 2023 के अनुसार भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के आस – पास के क्षेत्रों में खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है।
- भारत में ओडिशा का केंद्रपाड़ा जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां मगरमच्छ की तीनों प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

मगरमच्छ संरक्षण परियोजना क्या है ?

- मगरमच्छ संरक्षण परियोजना भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के पारित होने के तुरंत बाद संयुक्त राष्ट्र और भारत सरकार द्वारा शुरू की गई थी।
- इसका प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना, कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से मगरमच्छों की संख्या को बढ़ावा देना और प्राकृतिक वातावरण में नवजात शिशु के जीवित रहने की कम दर का समाधान करना है।
- इस परियोजना के तहत भारत में 34 स्थानों पर प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जिनमें खारे पानी मगरमच्छों या समुद्री मगरमच्छों (क्रोकोडाइलस पोरोसस) का विशेष ध्यान रखा गया है, जैसे कि भारत में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान।
- यह परियोजना मगरमच्छों के संरक्षण और पुनर्वास के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके तहत वन्यजीवों की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी और मगरमच्छ के संरक्षण को बढ़ावा दिया जा रहा है।

भारत में मगरमच्छों की वर्तमान संख्या और उसका वितरण :

- मगरमच्छ, जिन्हें अर्ध-जलीय सरीसृपों का एक गण / या यह अर्ध-जलीय सरीसृपों के समूह की एक प्रजाति माना जाता है, जो वर्तमान समय में दुनिया भर में लुप्तप्राय हो रहे हैं। भारत में भी इनकी संरक्षण की आवश्यकता है। **इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नलिखित है –**

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की संख्या :

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में खारे जल के मगरमच्छों की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी।
- भारत में वार्षिक नवीनतम सरीसृप जनगणना रिपोर्ट (2023) के अनुसार अब इसकी संख्याँ बढ़कर 1,811 हो गई है।
- भारत में मगरमच्छ की तीन प्रमुख प्रजातियाँ **मगर या मार्श मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पलुस्ट्रिस) :** यह अर्ध-जलीय सरीसृप भारत में पाए जाते हैं।
- **एस्टुआरिन या खारे पानी का मगरमच्छ (क्रोकोडाइलस पोरोसस) :** यह भारतीय खारे पानी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं या रहते हैं।
- **घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) :** यह भी भारत में पाए जाते हैं।

मानव – मगरमच्छ के बीच बढ़ता संघर्ष :

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में मगरमच्छों की बढ़ती संख्या के कारण मगरमच्छों और मनुष्यों के साथ संघर्ष बढ़ गया है।
- वर्ष 2014 से अब तक, 50 मौतें हो चुकी हैं, जिसके कारण अधिकारियों को हमलों को रोकने के लिए 120 नदी तटों पर बैरिकेड्स लगाने पड़े हैं।
- इस तरह के तमाम सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद भी मानव और मगरमच्छों के बीच संघर्ष जारी है और मगरमच्छों की सुरक्षा के लिए

नदी तटों पर कई उपाय अपनाए जा रहे हैं।

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मुख्य तथ्य :

भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान एक महत्वपूर्ण और अद्वितीय पारिस्थितिकी तंत्र है। उड़ीसा में स्थित इस पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु निम्नलिखित है –

भूगोल और वन्यजीवों का आवास :

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में 672 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है।
- यह सुंदरबन के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र है।
- इसकी मिट्टी लवणों से समृद्ध है और यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतःज्वारीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पतियों और प्रजातियों के लिए आवास है।
- यहां खारे पानी के मगरमच्छों का प्रजनन स्थल भी है।

गहिरमाथा समुद्र तट :

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के पूर्वी सीमा पर गहिरमाथा समुद्र तट है।
- यहां ओलिव रिडले समुद्री कछुओं की सबसे बड़ी कॉलोनी स्थित है।

वन्यजीवों की प्रजातियाँ :

- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान किंगफिशर पक्षियों की आठ प्रजातियों का भी आवास – स्थल है, जो एक दुर्लभ प्रजाति है।
- भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ने भारतीय वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह वन्यजीवों के आवास की सुरक्षा और उनके प्रजनन के लिए महत्वपूर्ण है।

भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत लुप्तप्राय मगरमच्छों और घड़ियालों के संरक्षण में समाधान / आगे की राह :

- भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को 1975 में विभिन्न राज्यों में शुरू किया गया था।
- इस परियोजना के तहत घड़ियाल और खारे पानी के मगरमच्छ के संरक्षण कार्यक्रम को पहली बार ओडिशा में लागू किया गया था।
- दक्षिण एशिया में सीमा पार सहयोग की अधिक संभावना है और इसकी आवश्यकता भी है।
- एक देश से दूसरे देश में या एक राज्य से दूसरे राज्य में जहां भी जानवरों की सीमा पार आवाजाही हो, वहां एक दूसरे के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान होना चाहिए।
- जैव विविधता संरक्षण में प्रकृति के लिए आवश्यक विभिन्न प्रजातियों और जीवों का संरक्षण शामिल है।
- जैव विविधता संरक्षण के प्राथमिक उद्देश्यों में प्रजातियों की विविधता को संरक्षित करना, पारिस्थितिक तंत्रों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना और व्यक्तिगत प्रजातियों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना शामिल है।
- इसके अतिरिक्त, जैविक विविधता का संरक्षण खाद्य श्रृंखलाओं की अखंडता और आवश्यक पारिस्थितिक समृद्धि को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

स्रोत – इंडियन एक्सप्रेस एवं पीआईबी।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. यह भारत में वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत आता है।
2. भारत में खारे जल के मगरमच्छों की संख्या वर्ष 1975 में 95 थी।
3. भारत में केंद्रपाड़ा जिले में मगरमच्छ की तीनों प्रमुख प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
4. घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस) भारत में नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – A

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के महत्त्व को रेखांकित करते हुए इसके के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा कीजिए। भारत की समृद्ध जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण में उन उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कीजिए। (UPSC- 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 2 के अंतर्गत ' भारतीय राजनीति और शासन व्यवस्था, भारतीय संविधान, सरकारी नीतियाँ ' खंड से और यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' डिजी यात्रा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में डिजी यात्रा फाउंडेशन के सीईओ ने बताया है कि हवाई अड्डों पर उपयोग की जाने वाली डिजी यात्रा तकनीक का विस्तार अब होटलों और ऐतिहासिक स्मारकों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर भी किया जा सकता है।
- इस तकनीक से इन स्थलों पर प्रवेश को भी सरल और सुविधाजनक बनाया जा सकेगा।
- सरकार ने हवाई यात्रा को और सुलभ बनाने के लिए चुनिंदा हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री की शुरुआत की है, जिससे यात्रियों को अपने दस्तावेज़ों के भौतिक रूप की आवश्यकता नहीं होगी और उनकी हवाई यात्रा की प्रक्रिया और अधिक तेज़ और अत्यंत सरल हो जाएगी।

डिजी यात्रा क्या है ?

- डिजी यात्रा एक उन्नत प्रौद्योगिकी है जिसमें यात्री अपनी पहचान की पुष्टि करने के लिए चेहरे का उपयोग करते हुए पेपरलेस और संपर्क रहित प्रक्रिया के माध्यम से हवाई अड्डों पर यात्रा करते हैं।
- इस तकनीक के साथ, यात्री के बोर्डिंग पास से जुड़े हुए चेकपॉइंट्स पर चेहरे की पहचान प्रणाली के आधार पर प्रवेश किया जाता है।
- यह बायोमेट्रिक इनेबल्ड सीमलेस ट्रैवल एक्सपीरियंस (BEST) के तहत आता है और हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके चेक-इन सेवाएं मिलती हैं, जिससे हवाई अड्डों पर यात्रिओं के लिए काग़ज़ रहित यात्रा अत्यंत सुलभ होती है।
- यह नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा समन्वित एक उद्योग-आधारित पहल है।
- इस प्रणाली का उपयोग होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थलों में भी अनुप्रयोग के रूप में किया जा सकता है।

डिजी यात्रा सेवाओं के विस्तार से संबंधित मुख्य चिंताएँ :

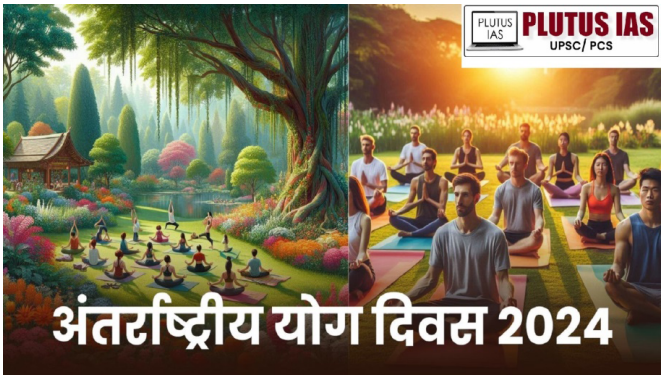

डिजी यात्रा से संबंधित मुख्य चिंताएँ निम्नलिखित है –

गोपनीयता संबंधी चिंताएँ और संशोधित नीतियां :

- इस योजना के तहत यात्रियों से संबंधित एक संशोधित नीति दस्तावेज जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसमें तीसरे पक्ष के विक्रेता के डेटा तक पहुंच से संबंधित मुद्दों को स्पष्ट किया जाएगा और उन शर्तों को भी स्पष्ट किया जाएगा जिनके तहत 24 घंटे के भीतर अनिवार्य डेटा स्पष्टीकरण की प्रक्रिया से छूट दी जा सकती है।
- इससे सरकार को लोगों के यात्रा पैटर्न / प्रणाली के संबंध में जानकारी मिल सकती है। जिससे नागरिकों के ' **निजता का अधिकार** ' प्रभावित या उसका उल्लंघन हो सकता है।

डेटा सुरक्षा :

- डिजी यात्रा को होटलों और सार्वजनिक स्थानों तक विस्तारित करने से डेटा सुरक्षा बढ़ेगी।
- इस उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा पारंपरिक पहचान सत्यापन विधियों के विपरीत, जिनमें अक्सर अनएन्क्रिप्टेड दस्तावेजों को साझा करना शामिल होता है, डिजी यात्रा आईडी में व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य जानकारी शामिल नहीं होती है।
- इस योजना के तहत यह प्रणाली केवल हैश मान या संख्यात्मक पहचानकर्ता को बरकरार रखती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि यात्रियों का नाम, आधार संख्या, फेस स्कैन और पासपोर्ट नंबर जैसे व्यक्तिगत डेटा लीक नहीं हो सकते हैं।

विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित करना :

- विदेशी पर्यटकों के लिए यात्रा करने के दौरान उनके दायित्वों की जानकारी देना अत्यन महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि वे अपनी यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बना सकें। विदेशी पर्यटकों को अपने आगमन और प्रस्थान की सूचना निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी होती है, जिससे उनकी सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा

हो सके।

- वर्तमान में, पाकिस्तान जैसे कुछ देशों के नागरिकों को अपने आगमन और प्रस्थान की सूचना 24 घंटे के भीतर निकटतम पुलिस स्टेशन में देनी होती है ।
- इसके अतिरिक्त,180 दिनों से अधिक के वीज़ा वाले अन्य देशों के पर्यटकों को विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) में पंजीकरण कराना आवश्यक होता है। यह उनके यात्रा के दौरान उनकी सुरक्षा और अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।
- डिजी यात्रा योजना के तहत विदेशी पर्यटकों को अपने वर्तमान समय की जानकारी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह नियम विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकते हैं। यदि आप विदेशी पर्यटक हैं, तो आपको अपने यात्रा के दौरान स्थानीय नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है।

कार्यान्वयन मंत्रालय :

- यह परियोजना भारत के नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंतर्गत डिजी यात्रा फाउंडेशन द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।
- डिजी यात्रा फाउंडेशन एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, जिसमें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और निजी हवाई अड्डों के संघ शामिल हैं।
- इस गैर-लाभकारी निजी कंपनी में निजी हवाई अड्डों के संघ की %74 हिस्सेदारी और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की %26 हिस्सेदारी है।

डिजी यात्रा का विस्तार :

- दिसंबर 2022 में शुरू की गई इस पहल में वर्तमान में 14 हवाई अड्डे शामिल हैं, और 2024 के अंत तक 15 और हवाई अड्डों को जोड़ने की योजना है।
- इस विस्तार से उन पर्यटकों के यात्रा अनुभव में काफी सुधार होगा जिन्हें होटल में चेक-इन और पुलिस सत्यापन के लिए अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, ताजमहल देखने आने वाले पर्यटकों को इस तकनीक से लाभ मिल सकता है।
- डिजी यात्रा फाउंडेशन के सीईओ ने बताया कि इस सेवा का विस्तार करने के लिए पर्यटन मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ चर्चा चल रही है। वर्ष 2022 में इसकी शुरुआत के बाद से, वर्तमान में इसके तहत 14 हवाई अड्डे शामिल हैं, और 2024 के अंत तक 15 और अतिरिक्त हवाई अड्डों को इसके तहत शामिल किया जाएगा।
- इसके पहले चरण में यह पहल सात हवाई अड्डों पर शुरू की गई थी, जिसमें दिल्ली, बेंगलुरु और वाराणसी पहले तीन हवाई अड्डे थे।
- इस योजना के तहत मार्च 2023 तक हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डों को भी इसमें शामिल किया गया था।
- इस सेवा के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय सहित विभिन्न सरकारी एजेंसियों के साथ चर्चा चल रही है।
- आने वाले समय में यह सेवा देशभर में उपलब्ध होगी और यात्रियों के लिए हवाई यात्रा करना और भी सुरक्षित और सुविधाजनक होगी।

डिजी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य :

डिजी यात्रा के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है –

- **यात्री आवाजाही के प्रवाह में सुधार करना :** डिजी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य है हवाई अड्डों पर यात्री प्रवाह में सुधार करना। इसके लिए बुनियादी ढांचे की दक्षता को बढ़ावा देना जरूरी है।
- **यात्री संख्या को समायोजित करना :** डिजी यात्रा के माध्यम से यात्री संख्या को समायोजित करने का उद्देश्य है। इसके लिए विभिन्न तरीकों से यात्री विकल्पों को प्रोत्साहित किया जाता है।
- **संभावित विस्तार के व्यापक दायरे का संकेत :** डिजी यात्रा के उपयोग से होटलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों तक संभावित विस्तार का संकेत मिलता है।
- यात्रा के दौरान गोपनीयता और डेटा सुरक्षा का ध्यान रखना भी अत्यंत जरूरी है।
- डिजी यात्रा सेवाओं का उपयोग करते समय, यात्री को अपने व्यक्तिगत जानकारी किसी से भी साझा करने के दौरान अपने व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए सतर्क रहना चाहिए।

डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार का महत्त्व :

- डिजी यात्रा (DiGi Yatra) जो यात्रियों को हवाई अड्डों पर सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से यात्रा करने की सुविधा प्रदान करता है।
- इस प्रणाली में यात्रियों को उनके चेहरे की पहचान के आधार पर बोर्डिंग पास से जुड़ी जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त होती है।
- यात्रियों को बिना किसी कागज़ के या संपर्क किए विभिन्न चेक पॉइंट से गुजरने की अनुमति मिलती है। इसके साथ ही, यह गोपनीयता और डेटा सुरक्षा जैसे मुद्दों से भी संबंधित है।
- डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार आधुनिक युग में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका महत्व विभिन्न पहलुओं से जुड़ा हुआ है। **जो निम्नलिखित है –**
- **अत्यंत सुविधाजनक और समय की बचत :** डिजी यात्रा सेवाएं यात्रियों को सुविधा और समय की बचत प्रदान करती हैं। यात्रा संबंधी जानकारी, यात्रा की बुकिंग, होटल रिज़र्वेशन, विभिन्न यात्रा विकल्पों के बारे में जानकारी इसे यात्रियों के लिए अधिक आकर्षक बनाती है।
- **अधिक संपर्क और सहयोग प्रदान :** डिजी यात्रा सेवाएं यात्रियों को अधिक संपर्क और सहयोग प्रदान करती हैं। ऑनलाइन समुदाय, समीक्षा पोर्टल्स और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के माध्यम से यात्री दूसरों के अनुभव और सुझावों से लाभ उठा सकते हैं।
- **बेहतर योजना और नियोजन :** डिजी यात्रा सेवाएं यात्राओं को यात्रा के लिए बेहतर योजनाओं और नियोजनों के लिए सुझाव प्रदान करती हैं। यह उन्हें यात्रा की संरचना, समय-सारणी और आरामदायक स्थलों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करने में मदद करती है।

PLUTUS IAS UPSC/ PCS

- **यात्रा अनुभव में सुधार :** डिजी यात्रा सेवाएं यात्राओं के अनुभव में सुधार लाती हैं। उन्हें बेहतर जानकारी, सुविधाएं, और यात्रा विकल्प प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी यात्रा सुरक्षित, आरामदायक और अधिक मनोरंजक होती है।
- **पर्यावरणीय प्रभाव :** डिजी यात्रा सेवाएं पर्यावरण को भी सुरक्षित करने में मदद कर सकती हैं। अधिक डिजीतलीकरण से यात्रा के लिए पेपरलेस विकल्प, इलेक्ट्रॉनिक टिकट और यात्रा संबंधी अन्य प्रक्रियाओं से प्रकृति और पर्यावरण को बचाने में अत्यंत सहायक होता है।
- इस प्रकार, डिजी यात्रा सेवाएं आधुनिक यात्रा के अनुकूल हैं और यात्रियों को एक सुविधाजनक, सुरक्षित और संतुष्ट यात्रा अनुभव प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

स्रोत – द हिंदू एवं इंडियन एक्सप्रेस।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार काग़ज़ रहित यात्रा को बढ़ावा देती है।
2. इस के तहत हवाई अड्डों पर बायोमेट्रिक्स का उपयोग करके चेक-इन सेवाएं मिलती हैं।
3. यह नागरिक उड़ान मंत्रालय द्वारा एक उद्योग-आधारित पहल है।
4. इसके तहत नागरिकों के ' निजता का अधिकार ' प्रभावित या उसका उल्लंघन हो सकता है।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इनमें से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – D

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. डिजी यात्रा सेवाओं का विस्तार योजना के प्रमुख प्रावधानों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह भारत में सार्वजनिक यात्रा सुविधा को किस प्रकार पारदर्शी, अत्यंत सुविधाजनक और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2022 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024

(यह लेख यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य परीक्षा के अंतर्गत सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र – 1 के ' इतिहास कला और संस्कृति, भारतीय वास्तुकला और भारतीय समाज, भारतीय समाज से संबंधित मुद्दे ' खंड से और प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत ' योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम, फिट इंडिया मूवमेंट, योग से कौशल विकास संबंधी पहल ' खंड से संबंधित है। इसमें PLUTUS IAS टीम के सुझाव भी शामिल हैं। यह लेख ' दैनिक करेंट अफेयर्स ' के अंतर्गत ' अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 ' से संबंधित है।)

खबरों में क्यों ?

- हाल ही में 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया था।
- इस वर्ष, 21 जून 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम **"स्वयं और समाज के लिए योग (Yoga for Self and Society)"** है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (International Yoga Day) हर साल 21 जून को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह दिन योग के महत्व और इसके स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। योग को शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देने, तनाव और चिंता को कम करने, सामान्य स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए जरूरी माना गया है।

योग दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और महत्त्व :

- योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द "युज" से निकला है, जिसका अर्थ "जोड़ना" या "एकजुट करना" है। योग मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है।
- योग का भारत से संबंध सदियों पुराना है। यह भारतीय संस्कृति और वेदों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज जब पूरी दुनिया योग के महत्व को समझ रही है, तो इसका श्रेय भारतीय योग गुरुओं को जाता है, जिनके प्रयासों से योग वैश्विक स्तर पर पहुंचा है।
- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का प्रस्ताव भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में रखा था।
- 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति देते हुए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया।

- इस प्रस्ताव को विश्व के कई देशों का समर्थन मिला और पहली बार 21 जून 2015 को विश्वभर में योग दिवस मनाया गया। इस दिन लाखों लोगों ने सामूहिक रूप से योग किया।
- वर्ष 2015 में नई दिल्ली के राजपथ पर आयोजित पहले योग दिवस समारोह ने दो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए।
- पहला रिकॉर्ड 35,985 लोगों के साथ विश्व का सबसे बड़ा योग सत्र था और दूसरा रिकॉर्ड एक ही सत्र में 84 देशों के लोगों की भागीदारी का था।
- पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "सद्भाव और शांति के लिए योग"थी।

21 जून ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस :

- योग दिवस 21 जून को मनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, जिसे ग्रीष्म संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है।
- 21 जून का दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है।
- ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य दक्षिणायन की ओर बढ़ता है, जिसे योग और अध्यात्म के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है।
- इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था।

योग और इसका महत्त्व :

- योग एक प्राचीन शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी उत्पत्ति भारत में हुई थी।
- शब्द "योग" संस्कृत से लिया गया है और इसका अर्थ है "जुड़ना" यानि शरीर और चेतना का मिलन।
- योग का अभ्यास शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है, मानसिक स्थिति को सुधारने में और आत्मा के विकास में सहायक होता है।
- योग के माध्यम से हम अपने शारीरिक और मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं, ध्यान के माध्यम से अपने आत्मा को पहचान सकते हैं, और आत्मा के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (World Health Organisation- WHO) ने भी अपने सदस्य देशों को योग का अभ्यास करने के लिए कहा है और इसे वर्ष 30-2018 की शारीरिक गतिविधि के लिए अपनी वैश्विक कार्य योजना में शामिल किया है।
- योग को अपने जीवन में धारण करने से हम कई शारीरिक और मानसिक बीमारियों से तो दूर रहते ही हैं, साथ – ही – साथ नियमित योगाभ्यास से हमारा स्वास्थ्य और शरीर भी अच्छा रहता है।
- योग से सांस की बीमारियां, मोटापा, गुर्दे, यकृत, मांसपेशियों में दर्द एवं डायबिटीज तथा उच्च रक्तचाप आदि से छुटकारा मिलता है और त्वचा में निखार आता है।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस क्यों मनाया जाता है ?

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मनाने का मुख्य उद्देश्य योग के अभ्यास के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभों को बढ़ावा देना है।
- योग एक प्राचीन भारतीय प्रथा है, जिसकी उत्पत्ति हजारों वर्ष पहले हुई थी। योग शारीरिक व्यायाम से कहीं आगे जाता है, इसमें मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है और समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा दिया गया है।
- योग एक प्राचीन भारतीय विज्ञान है जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए अभ्यास किया जाता है। योग के अभ्यास से शांति, स्वास्थ्य, और सुख की प्राप्ति होती है।
- योग का अभ्यास श्वास व्यायाम, ध्यान और नैतिक सिद्धांतों को एकीकृत करता है।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) योग को एक स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने, और गैर-संचारी रोगों (NCDs) को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में मान्यता देता है।
- योग सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जिसमें वर्ष 2030 तक शारीरिक निष्क्रियता में %15 सापेक्ष कमी लाना भी शामिल है।
- युवा मामले और खेल मंत्रालय ने योग को एक खेल अनुशासन के रूप में मान्यता दी है और वर्ष 2015 में इसे 'प्राथमिकता' की श्रेणी में रखा।
- योग दिवस का चयन 21 जून को किया जाता है, जो कि ग्रीष्म संक्रांति के समय पर होता है।
- ग्रीष्म संक्रांति के समय दिन की लम्बाई सबसे अधिक होती है और रात की लम्बाई सबसे कम होती है। योग के इस विशेष दिन को चुनने का उद्देश्य यह है कि इस समय पर पृथ्वी की ऊर्जा को अधिकतम रूप से उपयोग किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा योग से संबंधित शरू की गई अनेक पहल :

एम-योग एप :

- भारत के प्रधानमंत्री ने 'एक विश्व, एक स्वास्थ्य' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एम-योग एप की घोषणा की है। यह एप विश्व स्वास्थ्य

संगठन (WHO) और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के सहयोग का परिणाम है, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध, और होम्योपैथी शामिल हैं।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस (IDY) के लिए नई वेबसाइट :

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से संबंधित अद्यतन और प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एक नया वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। यह वेबसाइट आगंतुकों को चर्चाओं पर नज़र रखने और उनमें भाग लेने के लिए सभी सोशल मीडिया इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म भी प्रदान करती है। यह पोर्टल स्वच्छ भारत, मेक इन इंडिया आदि महत्वपूर्ण वेब पेजों से भी जुड़ा हुआ है।

खेल अनुशासन के रूप में मान्यता प्राप्त योग :

- भारत में खेल मंत्रालय ने विभिन्न खेल विषयों की समीक्षा के बाद योग को एक खेल अनुशासन के रूप में मान्यता दी है और इसे सितंबर 2015 में 'प्राथमिकता' श्रेणी में रखा है।

योग संबंधी सामान्य नियम :

- आयुष मंत्रालय ने अपने 'सामान्य योग नियम' में प्रमुख योग 'साधनाओं' जैसे यम, नियम, आसन आदि को सूचीबद्ध किया है।

योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम :

- ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल (B&WSSC) सीबीएसई विद्यालयों के लिए योग में व्यावसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम का संचालन करती है। B&WSSC को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में एक गैर-लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया है।

कौशल विकास संबंधी पहल :

- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के माध्यम से हजारों उम्मीदवारों को योग प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षण दिया गया है।

फिट इंडिया मूवमेंट :

- योग फिट इंडिया मूवमेंट का भी हिस्सा है। फिट इंडिया मूवमेंट एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में शारीरिक गतिविधियों और खेलों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित करना है।

प्रारंभिक परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।

1. वर्ष 2024 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का 9वें संस्करण का आयोजन किया गया था।
2. 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया।
3. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को 21 जून को मनाने का मुख्य कारण 21 जून का दिन साल का सबसे लंबा दिन होता है।
4. पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम "सद्भाव और शांति के लिए योग" थी।

उपरोक्त कथन / कथनों में से कौन सा कथन सही है ?

A. केवल 1, 2 और 3

B. केवल 2, 3 और 4

C. इन्में से कोई नहीं।

D. उपरोक्त सभी।

उत्तर – B

मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न :

Q.1. अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए यह चर्चा कीजिए कि यह मनुष्यों के स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार करने और गैर-संचारी रोगों (NCDs) को नियंत्रित करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में कैसे कार्य करता है? तर्कसंगत मत प्रस्तुत कीजिए। (UPSC CSE – 2019 शब्द सीमा – 250 अंक – 15)